राज्यपाल मध्यप्रदेश डॉ. बलराम जाखड़ का भाषण

मध्यप्रदेश विधानसभा का अधिवेशन 14 फरवरी 2006 को राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़ के अभिभाषण से शुरू हुआ। विधानसभा में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये नई औद्योगिक नीति पर अमल कर अधोसंरचना के विकास की दिशा में ठोस प्रयास किये हैं। बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी ठोस पहल की गयी है। उद्योग मित्र योजना लागू कर समस्याग्रस्त उद्योगों को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है। बीना रिफायनरी प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हुआ है और पीथमपुर में आटो टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना को मंजूरी मिली है। सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रदेश में निवेश करने के लिये आमंत्रित कर रही है। इस दिशा में फिक्की के सहयोग से डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश' का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल मे कनवेन्शन एंड ट्रेड सेंटर तथा ग्वालियर में हैबीटाट सेंटर की स्थापना की जा रही है। मेरी सरकार की सक्रिय पहल के फलस्वरूप भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र देवास को फर्मास्युटिकल्स उत्पादा के निर्यात के लिये प्रदेश का प्रथम 'टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' घोषित किया है। देश का पहला ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र इन्दौर के नाम से विकसित किया जा रहा है। ग्वालियर में भी एस.ई.जेड. स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। इन्दौर में क्रिस्टल आई.टी. पार्क को केन्द्र सरकार ने आई.टी.एस.ई.जेड. घोषित किया है। नई सरकार द्वारा निर्मित उद्योग मित्र वातावरण से दो वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के नये निवेश प्रस्ताव मिले हैं जिन पर कार्रवाई जारी है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करना मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसक तहत दस नये जिलों में जिला अस्पताल खोले गये हैं। उन सभी 41 विकासखण्डों में, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था नहीं थी वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर दिये गये हैं

स्कूल शिक्षा

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने स्कूली शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखा है। इसमें गुणात्मक सुधार तथा विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्वालिटी ' शुरू किया गया है। इसके लिये दूरवर्ती प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये लगभग पचास हजार संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 46 लाख बालिकाओं को निःशुल्क गणवेष उपलब्ध कराए गए है कक्षा एक से आठ तक के एक करोड़ 6 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आठवी पास कर दूसरें गांव में नौवी कक्षा में प्रवेश लेने वाली 37 हजार से अधिक बालिकाओं के निःशुल्क साइकिले वितरित की जा रही है। माध्यामिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उदेष्य से विकासखण्ड मुख्यालयों में एक शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। कक्षा 9वी एवं कक्षा 11वी के प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा तैयार कर स्थानीय परीक्षाएं आयोजित करने का नवाचार किया जा रहा हैं।

बालिका शिक्षा

राज्यपाल ने कहा के मेरी सरकार ने बलिका शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया है। बलिकाओं का उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिये 'गांव की बेटी योजना ' लागू की गई है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक गांव से बारहवीं कक्षा की प्रथम श्रेणी में अव्वल एक बलिका को उच्च शिक्षा के लिये 500 रूपयें महीना देने का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को मार्गदर्षन देने के लिये स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्षन योजना प्रारम्भ की गई है। उच्च शिखा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये दूरस्थ अंचलों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की योजना है। महाविद्यालय में गुणवत्ता लाने के लिये प्रदेश के महाविद्यालयों का मूल्यांकन कर उनके उन्नयन का अभियान चलाया गया है। एजूसेट के माध्यम से महाविद्यालयों में सेटेलाइट टर्मिनल्स लगाकर वर्चुअल कक्षाओं के प्रसारण की व्यवस्था की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी

मेरी सरकार ने आम लोगों की समस्याओं तथा शिकायतों के तेजी से निराकरण और प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा दिया

है। प्रशासन को संवेदनशील एवं जनोन्मुखी बनाने के लिये सुराज अभियान ' आरम्भ किया जा रहा है। जन शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिये टेली समाधान ' एवं समाधान ऑनलाइन ' जैसे अभिनव कदम उठाये जा रहे हैं। विकासखण्ड और जिला स्तर पर नियमित रूप से समाधान शिविरों ' का आयोजन किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय मिशन

मेरी सरकार समाज सेवी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के सहयोग से निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों तथा अनाथ कन्याओं के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के लिये जिलों में दीनदयाल अंत्योदय मिशन प्रारंभ करेगी। मिशन के अंतर्गत अनाथ तथा निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह की योजना भी प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश में निराश्रित निधि से 21 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों का भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रों के समान उन्नयन किया गया है। अभिभावकों की भूमिका तय करने के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर अभिभावक संघ स्थापित किये जा रहे हैं।

नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति

मेरी सरकार प्रदेश के लिये नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति बना रही है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये इन्दौर में साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क बनाया गया है। भोपाल एवं ग्वालियर में भी पार्क निर्माण किया जाएगा। डिजीटल सूचना के संचार के लिये राज्य में स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को सेवायें एवं जानकारी सुगमता से हासिल होगी।

सूचना का अधिकार

मेरी सरकार ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सूचना आयोग का गठन तथा अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। आयोग ने माह अक्टूबर से कार्य शुरू कर दिया है।

पेयजल

मेरी सरकार ने इस वर्ष 10 हजार से अधिक ऐसी बसाहटों में जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं हत्या अपर्याप्त है, वहां पेयजल व्यवस्था की है। इसी प्रकार शासकीय भवन वाली 5 हजार से

ज्यादा ग्रामीण शालाओं में पेयजल की व्यवस्था की है। समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 3 लाख 50 हजार से अधिक व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा पाठशालाओं म शौचालय बनाये जा रहे हैं। पेयजल में फ्लोराइड एवं खारे पानी की समस्या के निदान के उपाय किए जा रहे हैं।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन

मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को प्राथमिकता दी है। इस वर्ग की छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये करीब एक लाख 50 हजार कन्याओं को कन्या सारक्षता प्रोत्साहन का लाभ दिया गया। इसके साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति तथा सिविल सेवा परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष विभाग द्वारा संचालित प्री-मेट्रिक छात्रावासों में कम्प्यूटर प्रदान किये जायेंगे।

वक्फ संपत्ति की सुरक्षा

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के 538 हितग्राहियों को इस वर्ष 2 करोड़ रुपये तथा पिछड़ा वर्ग के 777 हितग्राहियों को 3 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने की कार्यवाही की है। पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये 8 संभागीय मुख्यालयों भोपाल इन्दौर जबलपुर ग्वालियर मुरैना रीवा, उज्जैन तथा सागर में सौ सीटर छात्रावास भवन के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के लिये छात्रावास भवन निर्माण की कार्यवाही जारी है। मेरी सरकार न वक्फ की सम्पत्ति की सुरक्षा के कदम उठाए हैं।

कानून का राज्य

मेरी सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना है। पुलिस को जनोन्मुखी एवं संवेदनशील बनाने के लिये मेरी सरकार कटिबद्ध है। पुलिस के आधुनिकीकरण की केन्द्र प्रवर्तित योजना में 98 करोड़ 95 लाख रुपये की योजना मंजूर हुई है। इससे वाहन उपकरण दूरसंचार उपकरण एवं अन्य आधुनिकीकरण के कार्य किये जा हैं। सरकार द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत थाना भवनों, महिला प्रसाधन कक्षों के निर्माण पर लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा मृत सैनिकों के आश्रितों और विकलांग सैनिकों को एक करोड़ 63

लाख रुपय की मदद दी गयी है। एक अभियान चलाकर 2 लाख बच्चों को यातायात का प्रशिक्षण दिया गया।